एविएशन सेक्टर में 96,000 करोड़ निवेश : नायडू

पिछले 5 वर्षों में यात्री संख्या में 9% की वार्षिक वृद्धि, उड़ान योजना से जोड़े गए 637 रूट : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को संसद को बताया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने अपने पब्लिक-प्राइवेट- पार्टनरशिप (पीपीपी) वेंचर्स के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच भारत के विमानन क्षेत्र में रुपए 96,000 करोड़ का निवेश किया है.

यात्री संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि- वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय हवाई अड्डों पर कुल 41.2 करोड़ यात्रियों का आवागमन हुआ, जिसमें 7.7 करोड़ अंतरराष्ट्रीय और 33.5 करोड़ घरेलू यात्री शामिल रहे. इसमें सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वर्तमान में देश में हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रम सहित 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं. इस अवधि के दौरान, शेड्यूल्ड भारतीय ऑपरेटरों ने 835 घरेलू और 251 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन किया.

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा- आरसीएस-उड़ान योजना- नायडू ने बताया कि 2016 में, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और हवाई यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) शुरू की थी. इस योजना के शुरू होने के बाद से, 637 आरसीएस मार्ग चालू हो चुके हैं, जो 92 अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले एयरपोर्ट्स को जोड़ते हैं, जिनमें 15 हेलीपोर्ट और दो वाटर एयरोड्रम शामिल हैं.

बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और नए हवाई अड्डे

मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा एयरपोर्ट्स पर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार एक सतत प्रक्रिया है, जो यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और सुरक्षा आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के विकास के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स (जीएफए) नीति, 2008 भी तैयार की है. हालांकि, केंद्र को इस नीति के तहत महाराष्ट्र के पालघर या मध्य प्रदेश के पचमढ़ी या मटकुली में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए संबंधित राज्य सरकार या किसी भी एयरपोर्ट डेवलपर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

बिजली क्षेत्र में 65 लाख करोड़ जरूरत

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता) देश में बिजली की मांग अगले 10 वर्षों में बढ़कर चार ट्रिलियन यूनिट पहुँच जायेगी जिसे पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में 65 से 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.

ओमनीसाइंस कैपिटल द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में साल 2035 तक 1,300 से 1,400 गीगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता स्थापित किये जाने की संभावना है. इसके लिए 65 से 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी. इसमें पारेषण ग्रिडों और स्मार्ट मीटर लगाने पर करीब 15 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. ओमनीसाइंस कैपिटल के अध्यक्ष और मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर अश्विनी शामी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ते झुकाव को देखते हुए बुनियादी ढाँचे में 65 लाख करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा अवसर है.

बिजली की मांग 4 ट्रिलियन यूनिट तक पहुँचेगी : रिपोर्ट

सौर ऊर्जा में सबसे बड़ा निवेश अनुमानित

रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा समय में देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 475 गीगीवाट है जिसमें 220 गीगावाट यानी 46 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा है.

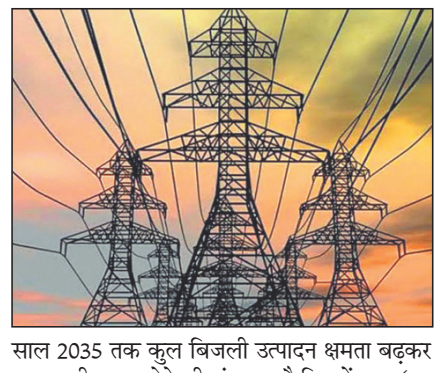

साल 2035 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,364 गीगावाट होने की संभावना है जिसमें 971 (71 प्रतिशत) गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा होगी.

ओमनीसाइंस कैपिटल का अनुमान है कि देश के ऊर्जा मिश्रण में इस बदलाव के लिए 54 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी. इसमें सौर ऊर्जा पर 23 लाख करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है जिससे उसकी स्थापित क्षमता में 458 गीगावाट की वृद्धि होगी. इस प्रकार प्रति गीगावाट के लिए पाँच हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. सौर के बाद पवन ऊर्जा क्षमता पर सबसे ज्यादा 11.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है.

तेजी के बावजूद बाजार लुढ़का

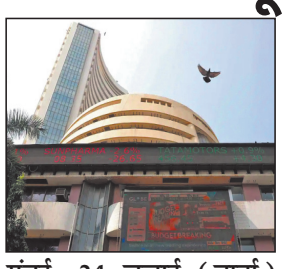

542 अंक पर गिरा सेंसेक्स

158 अंक पर लुढ़का निफ्टी

मुंबई, 24 जुलाई (वार्ता) विदेशों से मिले सकारात्मक रुख के बावजूद घरेलू स्तर पर निवेश धारणा कमजोर रहने से गुरुवार को शेयर बाजारों में बिकवाली हावी रही और प्रमुख सूचकांक 0.60 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गये.

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 542.47 अंक (0.66 प्रतिशत) टूटकर 82,184.17 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.63 अंक की गिरावट में रहा और बुधवार की तुलना में 157.80 अंक उतरकर 25,062.10 अंक पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की 30 में से 25 कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए. रिटेल क्षेत्र की कंपनी ट्रेंट का शेयर चार प्रतिशत के करीब लुढ़क गया. टेक महिंद्रा में 3.15 फीसदी की गिरावट रही. रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी के शेयर भी टूट गये. इटरनल में सबसे अधिक 3.44 प्रतिशत की तेजी रही. इसके अलावा टाटा मोटर्स, सन फार्मा, टाटा स्टील और टाइटन के शेयर भी बढ़त में बंद हुए.

चार साल में आईटीआर फाइलिंग में 36% उछाल

डिजिटलीकरण और नए ई-पोर्टल से कर प्रणाली में तेजी, संग्रह भी दोगुना हुआ

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता) नये ई-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत से पिछले चार साल में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह संख्या वित्त वर्ष 2020-21 के 6.72 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9.19 करोड़ पर पहुंच गयी है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रीय आयकर दिवस पर लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आयकर देश के आर्थिक तानेबाने की रीढ़ है. यह विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के निर्माण को शक्ति प्रदान करता है.आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि, जीएसटी और अन्य माध्यमों से ट्रैकिंग बढ़ाने के कारण आयकर संग्रह भी उसी तेजी से बढ़ा है. पिछले चार साल में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुने से भी अधिक हो गया है. वित्त वर्ष 2020-21 में यह 12.31 लाख करोड़ रुपये था जो 2024-25 में 27.02 लाख करोड़ रुपये हो गया है. मौजूदा सरकार ने पिछले 11 साल में कर आधार बढ़ाकर कर संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया है और डिजिटलीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है.

भारत में कर प्रणाली का इतिहास काफी पुराना है. कई शासकों ने अपने तरीके से कर लगाये, लेकिन मौजूदा कर प्रणाली की शुरुआत 24 जुलाई 1860 को हुई जब सर जेम्स विल्सन ने आयकर की अवधारणा को लागू किया. पिछले 165 साल में देश की कराधान प्रणाली में काफी बदलाव आया है और हाल में डिजिटलीकरण ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है - अनुपालना और कर प्रशासन दोनों मोर्चों पर.

देश में आयकर प्रणाली की विकास यात्रा में कई पड़ाव रहे हैं. अंग्रेजों द्वारा शुरू की गयी कर प्रणाली को कानूनी जामा 1922 में पहनाया गया जब विस्तृत आयकर अधिनियम लागू हुआ. इसके बाद केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1924 में बना. आजादी के बाद 1961 में आयकर अधिनियम अस्तित्व में आया जिसके तहत आज तक देश की प्रणाली का नियमन हो रहा है.

दूरसंचार पीएलआई से 4,305 करोड़ निवेश

अब तक 42 कंपनियों को योजना के तहत चुना गया

28,067 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला

नई दिल्ली, 24 जुलाई. दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की लाभार्थी कंपनियों ने 31 मई, 2025 तक कुल 4,305 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे 85,391 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जिसमें 16,414 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है.

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में यह जानकारी दी.मंत्री ने बताया कि इस निवेश से 28,067 लोगों को रोजगार भी मिला है. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत कुल 42 कंपनियों को लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है.

देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए, 700 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड सहित विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों में एक्सेस स्पेक्ट्रम 2022 और 2024 में आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटित किया गया है.

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने संचार क्षेत्र में इनोवेशन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं. डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर योजना के तहत, दूरसंचार विभाग ने स्वदेशी 5ज सहित उन्नत तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई द्वारा संचालित 126 परियोजनाओं को 108 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ समर्थन दिया है. इसके अतिरिक्त, देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है और अब तक 2,14,325 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है.

भारत में लॉन्च हुआ आईबीएम पावर11 सर्वर

आईबीएम ने भारत में सबसे उन्नत सर्वर - पावर11 प्रस्तुत किया

बैंकिंग, स्वास्थ्य, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से तैयार

नई दिल्ली, 24 जुलाई. भारत में आईबीएम ने अपना सबसे उन्नत पावर सर्वर आईबीएम पावर11 लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह सर्वर उद्यमों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए युग के अनुरूप बनाया गया है, जो वास्तविक समय में बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण, अद्वितीय विश्वसनीयता और सहज मिश्रित क्लाउड व्यवस्था प्रदान करेगा, साथ ही ऊर्जा की खपत और सूचना प्रौद्योगिकी लागत को कम करने में सहायक होगा.

आईबीएम इंडिया प्रणाली विकास प्रयोगशाला के महत्वपूर्ण सहयोग से विकसित, आईबीएम पावर11 को उन उद्यमों के लिए तैयार किया गया है जो बैंकिंग, खुदरा, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे जटिल, अत्यंत आवश्यक और डेटा-प्रधान कार्यों को संचालित करते हैं.

आईबीएम का कहना है कि पावर11 भारत के तीव्र गति से बदलते नियामक और डिजिटल परिदृश्य के लिए आदर्श है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार और डेटा संप्रभुता एक साथ आगे बढ़ते हैं. चिप पर ही विश्लेषण की सुविधा से उद्यम अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल वहीं चला सकते हैं जहाँ डेटा संग्रहित होता है,जिससे वास्तविक समय की समझ मिलती है और नियमों का पालन सुनिश्चित होता है.

अजय सेठ बीमा नियामक इरडा-आई के अध्यक्ष नियुक्त

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के अधिकारी सेठ पहले वित्त सचिव और आर्थिक मामले विभाग के सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री सेठ तीन साल तक या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने या अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे.

वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन राजधानी के भारत मंडपम में

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 25 से 28 सितंबर तक राजधानी के मंडपम में %वर्ल्ड फ़ूड इंडिया% के चौथे संस्करण की मेज़बानी करने जा रहा है.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को यहां विशेष कार्यक्रम में इस विशाल आयोजन के लिए प्रचार ब्रोशर, वेबसाइट और ऐप का अनावरण किया.पासवान ने ज़ोर दिया कि वर्ल्ड फ़ूड इंडिया महज़ एक व्यापार मेला नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी मंच है जिसका उद्देश्य भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि कि वर्ल्ड फ़ूड इंडिया का चौथा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 90 से ज़्यादा देशों, 2,000 से ज़्यादा प्रदर्शकों और खेत से लेकर खाने तक की पूरी खाद्य मूल्य श्रृंखला से जुड़े हज़ारों हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद है.

समाचार विशेष

भाजपा की जातिगत समीकरण साधने की कवायद

दलित बस्तियों में हो रहा संपर्क

पटना. बिहार की चुनावी लड़ाई में इस बार दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. इस चुनावी युद्ध में जीत उस गठबंधन की हो सकती है जो बिहार के सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ लेने में सफल होगा. इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा ने बिहार के दलितों को अपने पाले में लाने के लिए दलित बस्ती संपर्क अभियान चला रखा है.

इन संपर्क कार्यक्रमों में दलित समुदाय के पढ़े-लिखे युवाओं-विद्वानों के बीच यह विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार दलितों के उत्थान के लिए किस तरह कारगर साबित हुई है. बिहार में दलितों की आबादी लगभग 19 प्रतिशत है.

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ- केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर दलित समुदाय को साधने का काम किया है. भाजपा अपने दलित बस्ती संपर्क अभियान में उन दलित लाभार्थियों को भी बुला रही है जिन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया है. इसका उद्देश्य दलित समुदाय के बीच यह संदेश देना है कि केंद्र सरकार ने उनका जीवन स्तर बदलने का काम किया है. इसी तरह नीतीश कुमार सरकार ने भी बिहार में बेहतर काम किया है. भाजपा बिहार सरकार के लाभार्थियों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है.

नए पढ़े-लिखे युवाओं को अपने साथ जोड़ रही- कांग्रेस-राजद का महागठबंधन जातिगत जनगणना के मुद्दे के सहारे दलितों का वोट हासिल करने की रणनीति पर चल रहा है. राज्य के वामदल भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं. ऐसे में महागठबंधन की दावेदारी भी कमजोर नहीं है. लेकिन इसी विमर्श की काट के तौर पर भाजपा दलितों के बीच नए पढ़े-लिखे युवाओं को अपने साथ जोड़कर यह विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि एनडीए ने उनके लिए बेहतर कामकाज किया है.

पासवानों के बीच एनडीए का दबदबा

बिहार में पासवान दलित समुदाय की आबादी पूरे दलित समुदाय की लगभग 30.9 प्रतिशत है. दलितों के नेता के रूप में रामविलास पासवान इस समय भी सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं. उनका असर है कि चिराग पासवान की न केवल अपने क्षेत्र में लोकप्रियता है, बल्कि वे पूरे राज्य के दलितों के बीच लोकप्रिय हैं. वे भाजपा के साथ एनडीए में रहते हुए इस गठबंधन के लिए बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं.

संघ, भाजपा के नए हीरो हैं धामी

नई दिल्ली. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के नए हीरो के तौर पर उभर रहे हैं. संघ में भी उनकी खूब वाहवाही है तो भाजपा नेतृत्व भी उनके कामकाज को लेकर गदगद है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने निवेशक सम्मेलन में मिले प्रस्तावों को जमीन पर उतार दिया है.

उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को धरातल पर ला देना बहुत बड़ी बात है. गौरतलब है कि उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला था, जिसमें से एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आ गया है. अमित शाह ने उस समय कहा था कि निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारना मुश्किल होता है. तभी जब एक लाख करोड़ का निवेश आया तो शाह ने इस पर धामी की तारीफ की.

यह भी कहा गया कि राज्य में 81 हजार नई नौकरियों के अवसर बने हैं. इसी तरह उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है.

यह संघ और भाजपा का पुराना एजेंडा रहा है, जिस पर धामी की सरकार ने अमल किया है. उत्तराखंड मॉडल पर ही देश के दूसरे हिस्सों में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है. सो, शासन के अलावा वैचारिक मुद्दों पर भी धामी की तारीफ हो रही है. धामी की सरकार खोज खोज कर उत्तराखंड के मुस्लिम नाम वाले गांवों, कस्बों के नाम बदल रही है. ये सारे काम राज्य सरकार चुपचाप कर रही है.

तरनतारन सीट खाली घोषित

कहीं इसलिए तो नहीं हटाए धालीवाल; क्या है आप की रणनीति?

चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा ने तरनतारन के विधायक कश्मीर सिंह सोहल, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था, की सीट को खाली घोषित करके चुनाव आयोग को सूचित कर दिया है. अब यह सीट उपचुनाव करवाने के लिए खाली है.

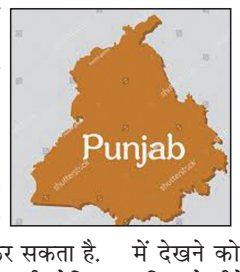

छह महीने के भीतर चुनाव आयोग किसी भी समय इस पर चुनाव घोषित कर सकता है. यह सीट 27 जून से खाली घोषित की गई है जिस दिन कश्मीर सिंह सोहल का निधन हुआ था. मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को वीरवार को मंत्रिमंडल से हटाने के पीछे तरनतारन में होने वाले उपचुनाव को भी देखा जा रहा है.

आम आदमी पार्टी जब भी यहां चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी, वह वहां के स्थानीय लोगों को उनकी ओर से पार्टी के चुने हुए विधायक को मंत्री पद देने का वादा कर सकती है. ऐसा पिछले दो उपचुनाव में देखने को मिला है. जालंधर पश्चिम से जीते मोहिंदर भगत और लुधियाना पश्चिम से जीते संजीव अरोड़ा को पार्टी ने मंत्री पद से नवाजा है.

विशेष पूर्वांचल की राजनीति में हलचल

योगी और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोमवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की. यह मुलाकात न सिर्फ दो बड़े राजनीतिक चेहरों के बीच लंबे समय से जमी बर्फ को पिघलाने का संकेत देती है, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर भी नई चर्चाओं को जन्म दे रही है.

बीते कई महीनों से बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच संवाद लगभग ठप पड़ा था. खासकर तब से जब सीएम योगी ने उनके सियासी विरोधी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के घर जाकर उनके पिता राजा आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी और वहां एक घंटे से ज्यादा समय बिताया. इसके बाद बृजभूषण की नाराज़गी को लेकर अटकलें तेज़ हो गई थीं और पार्टी के भीतर उनके भविष्य को लेकर भी असमंजस बढ़ गया था. लेकिन अब इस मुलाकात को उस सियासी नाराज़गी के पटाक्षेप के तौर पर देखा जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, बृजभूषण लंबे समय से सीएम योगी से संवाद बहाल करने की कोशिशों में लगे थे, और सोमवार को आखिरकार यह कोशिश रंग लाई.

इस मुलाकात को महज व्यक्तिगत संबंध सुधारने की पहल मानना जल्दबाज़ी होगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल एक निर्णायक भूमिका निभाता है. बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव पूर्वांचल के कैसरगंज, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में बेहद मजबूत है. ये जिले बीजेपी के लिए हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से अहम रहे हैं.

बीजेपी के भीतर समीकरणों का संतुलन

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी में आंतरिक खींचतान और धड़ों की राजनीति की खबरें सुर्खियों में रही हैं. ऐसे में बृजभूषण की योगी से मुलाकात को पार्टी नेतृत्व द्वारा एकजुटता और संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इस मुलाकात से यह भी संकेत मिलते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पुराने नाराज़ नेताओं को फिर से साधने और जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. इससे उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी संदेश जाएगा जो बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अब भी सक्रिय हैं.